

हॉटलाइन मेंटेनेस करने वाले कर्मियों का भत्ता हुआ दोगुना

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पांच ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी.ट्रांसको) में एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेस जॉब्स/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में दोगुनी बढ़ोतारी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये दिये जाने वाले भत्ते में भी दोगुनी बढ़ि कर दी गई है।

भत्ता अब दोगुना मिलेगा। पहले यह 6 रुपये से 40 रुपये के मध्य था, अब यह 12 रुपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब्स/ऑपरेशन के हिस्साब से मिलेगा। हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिये एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेस जॉब्स करने के लिये कर्मिकों को सहमति आवश्यक होती है। एम.पी.ट्रांसको द्वारा उन कर्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राप्तिकरण से प्रशिक्षण लियावाने के बाद ही वह जॉब्स/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब्स/हॉटलाइन ऑपरेशन अल्पतम जॉब्स भारी होने के कारण कर्मियों को यह भत्ता दिया जाता है। पहले यह सिक्की नियमित कर्मियों के लिए लागू था।

भोपाल में एनपीएस कर्मचारियों का प्रदर्शन 1 अप्रैल को

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नेशनल मूर्खमेंट फारू ओल्ड पेंशन स्कॉम के भोपाल जिला इकाई ने आंदोलन की घोषणा की है। नई पेंशन योजना के विरोध में संगठन ने 1 अप्रैल 2025 को विरोध प्रदर्शन का एलान किया है।

कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पुरुषी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। इस दिन सभी एनपीएस कर्मचारी काली पट्टी बांधक अपने कार्यालयों में काम करेंगे। कार्यालयों का विरोध दर्शकरण। साथ ही प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुरुषी पेंशन योजना की बहाली के लिए जापान से जापौंगे। भोपाल जिले के जिला अध्यक्ष सुश्रुत प्रसाद पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

विश्व जल दिवस पर सेंट जोसेफ कोलार में जागरूकता कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सेंट जोसेफ को-एड स्कूल कोलार रोड में आज विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेशनल केंटर कर (एनसीसी) के समर्थनों परापर्थना सभा के दौरान जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।

फैक्टेट्स ने एक प्रभावशाली नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नाटक में दिखाया गया कि बढ़ते प्रदूषण से जलसंचय प्रियल रहे हैं। यह स्थिति पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा बन रही है। प्रदूषण से पेंड़ों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। नदियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इनमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना शामिल है। फैक्टरियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता बताई गई। पेट्रोल-डीजल वाहनों के स्थान पर सीएनजी वाहनों के उपयोग पर बल दिया गया।

आंगनवाड़ियों में बर्तन खरीदी में गड़बड़ी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। आंगनवाड़ियों के बर्तन खरीदी में अपर्याप्त ने हड्डे पार कर दी। स्टील का लालस 162 रुपये, थारी 60 रुपये और चम्मच 38 रुपये में खरीदी गई। रीवा कमिशनर की जांच में शुरूआत में ही गड़बड़ी सामने आ गई। सिंगरीली के जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्वाचित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस भ्रात्याचार को लेकर सबाल पूछा था।

महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि आदेश अनुसार सामग्री प्रदाय की प्रक्रिया जारी है और भूतान अभी नहीं हुआ है। विधायक ने सावल के लिए बर्तन खेले बाजार से कई गुना अधिक दर पर जैम पोर्टल से खरीदे गए, जिससे सरकार को नुकसान हुआ।

जिले में यह खरीदी जिला कार्यक्रम अधिकारी एक ही फर्म से कर रहे हैं। सिंगरीली में प्रति केंद्र 30 थाली 610 रुपये की, 46500 नग लालस 162 रुपये में, चम्मच 38 रुपये में, 6200 नग

भाजपा विधायक सबनानी ने उठाया मुद्दाःपीएम आवास 6 साल तक लेट, लोग चुका रहे याज

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पांच ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी.ट्रांसको) में एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेस जॉब्स/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में दोगुनी बढ़ोतारी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेस जॉब्स करने के लिये कर्मिकों को सहमति आवश्यक होती है। एम.पी.ट्रांसको द्वारा उन कर्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राप्तिकरण से प्रशिक्षण लियावाने के बाद ही वह जॉब्स/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब्स/हॉटलाइन ऑपरेशन अल्पतम जॉब्स भारी होने के कारण कर्मियों को यह भत्ता दिया जाता है। पहले यह सिक्की नियमित कर्मियों के लिए लागू था।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर को पहल पर मध्यप्रदेश था, अब यह 12 रुपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब्स/ऑपरेशन के हिस्साब से मिलेगा। हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेस जॉब्स करने के लिये कर्मिकों को सहमति आवश्यक होती है। एम.पी.ट्रांसको द्वारा उन कर्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राप्तिकरण से प्रशिक्षण लियावाने के बाद ही वह जॉब्स/हॉटलाइन ऑपरेशन के लिये पात्र होता है।

जिन लोगों ने इसमें फलैट बुक किए हैं, उन्हें बैंक लोन की किस्त और ब्याज भरना पड़ रहा है और आवास भी नहीं मिले हैं। नगर निगम भोपाल निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रहा है। बाद से अब तक कुल 342 लोगों की राशि जमा कर दी है। जबकि में भी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह गंगा नगर आवास योजना के लिए जापान कर्मियों को भी बोर्डर रिपोर्ट दिया है।

इसके लिए गुजरात की कंपनी एमपीटी



दिया और इन्हें 18 महीने में पूरा काम करना है। मंत्री ने कहा कि 72 आवासों का निर्माण पूरा हो गया है और बाकी का काम दिसंबर 2025 तक करेंगे। ठेकेदारों को 6 बार समय भी दिया गया। इसके बाद भी काम नहीं हुआ तो उनके एपीएमेट को टर्मिनेट कर दिया गया है। नई कंपनी एसआरएस इन्फा को अक्टूबर 2023 में काम

मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिष्ठक उमंग सिंधार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर को जापान सोनपकर भाजपा उन्हें भी क्षेत्र के विकास के लिए ड्वलपमेंट फंड के 15-15 करोड़ रुपये की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि मप्र में भाजपा के विधायकों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए हर साल सोनपाने के लिए रुपये 15-15 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने कहा कि लोग केवल निर्माण में हो रही देरी से ही परेशान नहीं है। इसके अलावा उन्हें रजस्ट्री में 25 फीसदी की छूट नहीं दी जा रही है। अब तक कलेक्टर ने सूची नहीं भेजी है। उन्होंने गंगा नगर प्रोजेक्ट के तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि शहर में ऐसे 13 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें 12 नंबर बस स्टॉप, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, श्याम नगर, कोकता, हिनोतिया, कलखेड़ा, मालीखेड़ी, गरसलाखेड़ा आदि की स्थिति भी ऐसी ही। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट का काम भी समय वाले रुपये हो जाए।

मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नेता प्रतिष्ठक उमंग सिंधार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर को जापान सोनपकर भाजपा उन्हें भी क्षेत्र के विकास के लिए ड्वलपमेंट फंड के 15-15 करोड़ रुपये की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भाजपा के विधायकों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए हर साल सोनपाने के लिए 15-15 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने कहा कि लोग केवल निर्माण में हो रही देरी से ही परेशान नहीं है। इसके अलावा उन्हें रजस्ट्री में 25 फीसदी की छूट नहीं दी जा रही है। अब तक तकलीकरने के लिए गंगा नगर प्रोजेक्ट के तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि शहर में ऐसे 13 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें 12 नंबर बस स्टॉप, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, श्याम नगर, कोकता, हिनोतिया, कलखेड़ा, मालीखेड़ी, गरसलाखेड़ा आदि की स्थिति भी ऐसी ही। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट का काम भी समय वाले रुपये हो जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर विकित्सक डॉ. शर्मा को एयर एंबुलेंस से उपचार के लिए भेजा चेन्डर

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एस्ट्रोपाल में प्राथमिक केप एवं प्रस्तुति प्रोजेक्ट में यादव को एयर एंबुलेंस से चेन्डर भेजा जा रहा है। वे अति गंभीर स्थिति में कॉर्जेस्ट्रिव कॉर्डिंग के लिए चेन्डर भेजा जा रहा है। यह एयर एंबुलेंस से चेन्डर भिजवाने के लिए 100% प्रोजेक्ट के लिए एयर एंबुलेंस सेवा को अतिमान अंतर्गत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. शर्मा की गंभीर स्थिति में एयर एंबुलेंस सेवा को अतिमान अंतर्गत है। सिंगरीली में एयर एंबुलेंस सेवा एसी गंभीर स्थितियों में देवदतूत सिँद्ध हो रही है। गंभीर मरीजों के लिए यह सेव

बस और सफारी कार की टक्कर, तीन लोग घायल, भैसरहा पेट्रोल पंप के पास हादसा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। रीवा-शहडोल मार्ग पर भैसरहा पेट्रोल पंप के पास रविवार दोपहर 3.30 बजे बस और सफारी गाड़ी में आपने-सामने की टक्कर हो गई।

हादसे के तहाँ जब सफारी गाड़ी पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप से बाहर निकल रही थी। तेज रफ्तार में आ रही बस सफारी से टक्कर गई। टक्कर में बस का आगता द्विस्तरा और सफारी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

सफारी चालक रमेश जयसवाल को सिर में छोट आई है। उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार महेंद्र तिवारी और हरेंद्र कुश्वाह भी घायल हुए हैं। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें



गांजा बेचते एक आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने 650 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के कुसमी थाना पुलिस ने मेडो गांव में रविवार को एक व्यक्ति को गाजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 650 ग्राम गांजा बारामद हुआ है। इसकी कीमत बाजार में 11 हजार रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री से मिली सूचना के बाद चालक ने बारामदी भौंपेश कुमार बैंसे का कार्रवाई की।

पुलिस अधिकारी के निर्देश पर विशेष इस आधार पर आगे की जांच की जा रही है। टीम ने मेडो गांव नदी पर प्रकाश सिंह, रामेश्वर सिंह, कन्दलेश प्रजापति समेत आरक्षक दिव्येश सिंह, दिनकर द्विवेदी, पंकज सिंह और शिवराम वैश्य शामिल थे। एकट के तहत मामला दर्ज किया है।

60 वर्षीय देवचरण अपने घर से ही गांजा बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एकट के तहत मामला दर्ज किया है।

क्षेत्र में लगातार हो रही छापेमारी से नशा तस्करों में हड्डकप मचा हुआ है।



खूंटा उखाड़ने के शक में दंपती को लाठी-डंडों से पीटा, तीन लोगों पर केस दर्ज, सीधी जिले के माटा गांव की घटना

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के माटा गांव में केवट दंती पर दंडों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो रविवार को सामने आया। पीड़ित परिवार ने मज़ाली थाने में शिकायत की है। पुलिस ने धारा 155 के तहत मामूली अपराध दर्ज किया है। पीड़ित बबूल केवट ने बाताया कि भीमसंग मिश्र, पृष्ठ मिश्र और मोहित मिश्र ने उन्हें और रामकृष्णपाल केवट को लाठी-डंडों से पीटा। आरोपियों ने पुरानी रीजेंस और खुंटा उखाड़ने के शक में यह हमला किया।

पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले भी दंडों ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस के सख्त कार्रवाई नहीं करने से आरोपी बेंचोंप हैं। थाना प्रभारी से शिकायत के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में युवाओं के पंजीयन की अतिम तिथि 31 मार्च

सीधी। प्राचीय औंगोलिक प्रशिक्षण संस्था ने जाकारी देकर बताया है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का देवेंश युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अंतर्गत प्रदान कर रोजानाप्रक बनाना है। जिससे युवाओं को वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और अंग्रेजी को बोलने के लिए तीमें विशेषज्ञों को बोलने के लिए बढ़ावा देना है। योजना में 21 वर्ष से 24 वर्ष आगे के युवा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आर्टीआई, पॉलीटेक्निक या प्रैक्टिशियन किये हैं और वे किसी अंग्रेजिस या पॉलीकालिंक रोजगार में न हों। ऐसे युवा पर्जीनार के सफरों के दौरान आरोपियों को इंटर्नशिप की अवधि में 5000 रुपये प्रति माह स्टायर्ड और एकलाइन 6000 रुपये प्रति माह स्टायर्ड और एकलाइन 6000

हुई है। पीड़ितों का मेंडिकल परीक्षण करता है। परिवार का आरोपी है कि आरोपी दंडों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। इसी कारण पुलिस उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई करने से बच रही है। यह घटना तीन दिन पुरानी रीत बाटाई जा रही है।

न्याय के लिए भटक रहा परिवार का कहना

है कि उन्हें लगातार धमाकियां दी जा रही हैं। ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जर्द जर्द सजा मिल कर भावित्य में इस तरह की घटनाएँ न हों। यहाँ प्रभारी मज़ाली लीपक सिंह बघेला ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ था जहाँ धारा 155 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

प्रशासन से न्याय की मांग: पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री और

50 लाख की सरकारी जमीन खाली कराई हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। मप्र हाई कोर्ट के आदेश पर सिंगरौली नगर निगम ने बाईं नंबर 31 दोटी में करीब 50 लाख रुपए की अतिक्रमण के अंतर्गत प्रदान कर रोजानाप्रक बनाना है। जिससे युवाओं को वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और अंग्रेजी को बोलने के लिए बढ़ावा देना है। योजना में 21 वर्ष से 24 वर्ष आगे के युवा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आर्टीआई, पॉलीटेक्निक या प्रैक्टिशियन के अंतर्गत देवेंश युवाओं को बोलने के लिए बढ़ावा देना है। योजना में नहीं मौजूद है। ऐसे युवा पर्जीनार के सफरों के दौरान आरोपियों को इंटर्नशिप की अवधि में 5000 रुपये की मांग है। प्रति माह स्टायर्ड और एकलाइन 6000 रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

इससे पहले बेलौंजी कार्रवाई के दौरान एसडीएम सजन वर्मा, आयुक्त डॉ.के. शर्मा, वहसीलदार सविता यादव और विध्यनार थाना प्रभारी अर्चना निकारी और खनन पर प्राप्ति की गयी है। इससे पहले बेलौंजी कार्रवाई के दौरान एसडीएम सजन वर्मा, आयुक्त डॉ.के. शर्मा, वहसीलदार सविता यादव और विध्यनार थाना प्रभारी अर्चना निकारी और खनन पर प्राप्ति की गयी है।

मार्च में यह निगम की दूसरी बड़ी जांच की जारी है। इससे पहले बेलौंजी

बसों और लोडिंग गाड़ियों की फिटनेस जांच सिंगरौली आरटीओ के उड़दस्ता ने देखे खिड़की, दरवाजे और पैनिक बटन, नियमों के उल्लंघन पर वसूला जुर्माना



6 पिकअप से 23 मवेशी मिले दो पिकअप पलटे, अमलाई पुलिस ने की कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। सिंगरौली जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए आरटीओ विभाग का उड़दस्ता कंसर्ट गेट से खनहना तक लगातार जांच कर रही है। टीम मुख्य रूप से यात्री बसों में आपातकालीन खिड़की, दरवाजे, पैनिक बटन और कार्रवाई की जांच कर रही है। इसमें बस के बेक और टायर की नियमित जांच, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, नियमानुसार बालवान करना जैसा कार्रवाई किया गया है। बाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बाहन का नियमित रखरखाव करें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखवा रहें।

चेक पॉडट प्रभारी अनिमेष जैन के नेतृत्व में उड़दस्ता टीम कसर गेट से खनहना तक लगातार जांच कर रही है। अनिमेष जैन ने बताया कि बस चालकों को दिर्देंश दिए जा रहे हैं। इनमें बस के बेक और टायर की नियमित जांच, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, नियमानुसार बालवान करना जैसा कार्रवाई किया गया है। बाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बाहन का नियमित रखरखाव करें और सभी जरूरी दस्तावेज की जांच कर रही हैं।

अमलाई प्रभारी अनिमेष जैन ने बताया कि अनुसारा सभी वाहनों में 23 मवेशी बरामद किए गए। पुलिस ने जैन ने आज आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। एसपी रामजी श्रीवास्तव के नियंत्रण में फरार के लिए विशेष टीम का पुलिस ने अन्तर्गत की तरफ से आ रहे समिध वाहनों को रोकने के लिए नाकेबंदी की थी। पुलिस को देखते ही सभी वाहन चालकों ने तजीज से भागने का प्रयास किया। इस दौरान दो पिकअप वाहन जैन ने अनियंत्रित होकर भैंसरहा पलटे। एसपी रामजी श्रीवास्तव के नियंत्रण में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। आगे जांच करने में एक आरोपी को गिरफ्तार की जांच की जारी है।

उत्तेक्षणीय है कि इससे पहले जैन ने बताया कि अनियंत्रित होकर भैंसरहा पलटे। एसपी रामजी श्रीवास्तव के नियंत्रण में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था।

जैन ने बताया कि अनियंत्रित होकर भैंसरहा पलटे। एसपी रामजी श्रीवास्तव के नियंत्रण में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था।

तेजपुर के लिए विशेष टीम का नियंत्रण में एक आरोपी को गिरफ्तार की जारी है।

तेजपुर के लिए विशेष टीम का नियंत्रण में एक आरोपी को गिरफ्तार की जारी है।

तेजपुर के लिए विशेष टीम का नियंत्रण में एक आरोपी को गिरफ्तार की ज

विचार

बंगाल की सभी सीटों पर संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्कार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने का टास्क दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्कार्जुन खरगे ने पार्टी के नेताओं को पश्चिम बंगाल में जनाधार और संगठन को मजबूत करने की सलाह दी है।

दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय %इंदिरा भवन% में बृहदार को खरगे की अध्यक्षता और राहुल गांधी एवं केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार, वरिष्ठ नेता अंधीर रंजन चौधरी और दीपा दासमुंशी सहित बंगाल कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत बनाने की कांग्रेस की कावायद के साथ ही यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या कांग्रेस के मजबूत होने का खामियाजा पश्चिम बंगाल की सत्तास्थ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उठाना पड़ेगा? या फिर कांग्रेस की मजबूती से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो ममता बनर्जी विरोधी मतों के सहरे राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है।

इसके लिए हमें वर्ष 2016 और वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करना पड़ेगा। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी 294 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने 45.6 प्रतिशत वोट हासिल कर राज्य की 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को बोट भी ज्यादा मिले और सीटों की संख्या में भी बढ़ाते हुए 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 48.5 प्रतिशत वोट हासिल कर टीएमसी ने 213 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो 2016 में राज्य की 291 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही आ पाई थी और मत भी 10.3 प्रतिशत ही मिल पाया था। वहीं उस चुनाव में लेप्ट पार्टीयों के साथ मिलकर लड़ी कांग्रेस ने 12.4 प्रतिशत मत के साथ 44 सीटें जीती थी। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन सबसे ज्यादा शर्मनाक रहा। जबकि भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। पिछले चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 12.4 प्रतिशत से घटकर महज 3 प्रतिशत रह गया और पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई।

आखिर कब समझेंगे अपनी जिमेदारी?

समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सिलसिलेवार ढंग से जो संवैधानिक द्रामा रचाया जा रहा या चल रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद जिमेदार है, योंकि जनहित में प्रभावशाली कानून बनाने का जिमा उसी के ऊपर है। यदि उसने इस मामले में अबतक किसी तरह की कोई लापरवाही बरती है तो यह जन-बहस का मुद्दा है। इसलिए कुछ सुलगता हुआ सवाल यहां पर प्रारंभिक है! लेकिन जब हम संसद की बात करते हैं तो इसकी सीधी जिमेदारी सापेक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और उनके समूह की होती है। योंकि सा की अदलाबदली प्रायः इन्हीं के बीच होती रहती है। संसद के अलावा, हमारी सिविल सोसाइटी, मीडिया मठाधीश, अधिवक्तागण, शिक्षाविद, प्रबुद्ध कारोबारी तबका एवं विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक दबाव समूह भी इस स्थिति के लिए सामूहिक रूप से जिमेदार हैं, योंकि भले ही इनके पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है या फिर अलग-अलग प्रकार की कानूनी सहूलियत प्राप्त है, लेकिन जनमत निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती आई है।

यही वजह है कि जनता दिन-ब-दिन गरीब और उसके शासक लगातार अमीर होते जा रहे हैं। इनके अवैध धन से कहीं आतंकवादी, तो कहीं नक्सली व उग्रवादी फलपूल रहे हैं। भ्रष्टाचार, तस्करी, तबाला उद्योग, जबर्दस्ती हिंसा-प्रतीक्षा आदि मानवता विरोधी नीतियों या कायांपे पर निर्णयक चेक एंड बैलेंस के लिए कलाक की बात है। अखिर अनवरत संस्कृतिक दर्गाएँ और राजकोषीय लूट के लिए हमारी संसद नहीं तो कौन जिमेदार है, यक्ष प्रश्न है।

कायपीयी, फर्म, ट्रस्ट, एनजीओ आदि को अलग इकाई मानना और उनके लोकतांत्रिक विवाल होने पर उनके संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होना, उनकी या उनसे लाभान्वित लोगों की अन्य समर्पितों तक प्रशासनिक अंचंग का नहीं पहुंचना हमारी नीतितान विफलता नहीं तो क्या है? आज भू-संपदाओं में जो धोखाधड़ी मची हुई है, मौजूदा क्षेत्र में डिविटल धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है, इसके लिए अलग इकाई का बात है। अखिर अनवरत संस्कृतिक दर्गाएँ और राजकोषीय लूट के लिए हमारी संसद नहीं तो कौन जिमेदार है, यक्ष प्रश्न है।

कायपीयी, फर्म, ट्रस्ट, एनजीओ आदि को अलग इकाई मानना और उनके लोकतांत्रिक विवाल होने पर उनके संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होना, उनकी या उनसे लाभान्वित लोगों की अन्य समर्पितों तक प्रशासनिक अंचंग का नहीं पहुंचना हमारी नीतितान विफलता नहीं तो क्या है? आज भू-संपदाओं में जो धोखाधड़ी मची हुई है, मौजूदा क्षेत्र में डिविटल धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है, इसके लिए अलग इकाई का बात है। अखिर अनवरत संस्कृतिक दर्गाएँ और राजकोषीय लूट के लिए हमारी संसद नहीं तो कौन जिमेदार है, यक्ष प्रश्न है।

उनभव बताता है कि पुलिसिया भ्रष्टाचार, तस्करी कावायद, नक्सली व लेटलॉफी, प्रशासनिक पक्षपात, सियायी अंतिमता से समूचा भयांकर और परेशन है, लेकिन हमारे मानवीयों को अपनी जिमेदारियों का एहसास नहीं है। या वैसा कोई सजग व्यक्ति या समूह भी नहीं है जो इन लोकतांत्रिक मानवीयों को उनकी मौलिक शक्ति का एहसास दिलाए।

सबाल किसी जब की कोटी में भारी मात्रा में नेटों के मिलने का नहीं है और न ही उनके खिलाफ लोपापेती वाली प्रक्रिया युक्त करता है, बल्कि सुलगत हुआ सवाल यह है कि व्यवस्था के ऐसे जिमेदार तल्लों के खिलाफ निर्णयक कार्रवाई करने में हमारी संवैधानिक व्यवस्था किसी असहाय प्रतीत होती आई है और आज तक उसका सार्थक और सकारात्मक हल नहीं हूंडा जा सकता है। आपने देखा सुना होगा कि देश को लूटने वाले विदेशों में बस रहे हैं। ऐसे लोग हमारी कानूनी खामियों का फायदा उठाकर विदेशों में भौंक कर रहे हैं, क्योंकि उनके परोक्ष सियायी शह रखने वाले होने प्राप्त हैं। ऐसे यह है कि यदि मौजूदा लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था किसी सुख-शांति-समृद्धि सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं तो फिर उसके होने या न होने का क्या मतलब रह जाता है। इस नजरिए से आधुनिक लोकतांत्रिक भी अपनी अंतिम संसंगें प्राप्त होती है, और पैंचांपियों के नेतृत्व वाली नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, जिससे अमलोगों की त्रासदी और बढ़ेगी।



दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि समाज का यह जागरूक तबका और उनका जीवी संगठन राजनीतिक रूप से दलित-महादलित, औबीसी-एमबीसी, सर्वण-गरीब सर्वण, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक, आदिवासी-आर्य, अकालीयत-पसमादा, भाषा-क्षेत्र, अमोर-गरीब आदि विभिन्न गुटों में बंटा हुआ है, जो आभिजात वर्गीय सोच की हिफाजत का टूल्स बन दिया गया है।

वहीं, संसद द्वारा सही कानून बनाने और बनाए हुए कानूनों को लागू करने में नौकरशाही की बड़ी भूमिका रहती है। जबकि इन कानूनों की न्यायासम्मत समीक्षा करने और मतभेद या विवाद की स्थिति में अंतिम नियंत्रण देने की जिमेदारी

किसानों की लेकर कांग्रेस और 'आप' के बीच मतभेद उभरा ताकि जिमेदारी की विवालों की दलील के आधार पर किसी अंतिम निर्कर्ष तक पहुंचा जाता है। खास बात यह कि हमारी नौकरशाही के प्रशासनिक विवेक और न्यायपालिका के न्यायिक विवेक पर भी कोई सवाल उसी तरह से नहीं उठाना जा सकता है, जिस तरह से विधिविका के विधायी व प्रशासनिक विवेक और मीडिया के संपादकीय विवेक को मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त है।

कहने का तात्पर्य यह कि किसी भी लोकतांत्र की सफलता के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया का जागरूक और निष्पक्ष होना पहली शर्त है। मौजूदा दौर में धनपशुओं से सहयोग प्राप्त सिविल सोसाइटी यानी

किसानों को लेकर कांग्रेस और 'आप' के बीच मतभेद उभरा

पंजाब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों पर की गई प्रतिवाई के महेनजर प्रमुख 'ईडिया' ब्लॉक पर्याप्तियों का कांग्रेस और 'आप' के बीच संबंधों में मतभेद बढ़ गए हैं जिसमें कांग्रेस ने 'आप' के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के साथ-साथ भाजपा भासित केंद्र को भी कटघोरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। सरकार सिंह पंधरे और जगजीत सिंह डब्ल्यूएल सरकार के साथ बैठक से लौटे को नेतृत्व वाली समय में अवरुद्ध थे। कांग्रेस और संयुक्त किसानों मोर्चा 'एस.एस.' ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 'आप' और भाजपा ने कई कृषि नेतृत्वों को हिरासत में ले रखा है। अम चुनाव के बाद से खाजपा और आर.एस.एस. के बीच संबंध तात्पर्य हैं, जहां मोर्ची के नारे, 'अबकी बार चार सौ पार' को अति

